not the Prime Minister who decided, it, it was the Speaker who decided it.

MR. SPEAKER : You might be thinking Professor...(*Interruptions*)...

PROF. MADHU DANDAVATE : He is casting aspersions against the Speaker of the previous Lok Sabha.

MR. SPEAKER : No questions. I know what I am doing.

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, he is casting reflections against the Speaker of the previous Lok Sabha. He said those were the dark days.

MR. SPEAKER : I am guided by the rules and I am the last person to break the rules, because it will boomerang on me, if I break the rules.

PROF. MADHU DANDAVATE : I am happy about it, but you don't allow it.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Sir, I am on a point of order. My point of order is when a privilege motion is...

MR. SPEAKER : That is all right. That is not allowed. It is over-ruled.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : Sir, I am on a point of procedure.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Mr. Halder, it is all right now. I have over-ruled you.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : Sir, privilege motion cannot be treated as a half-an-hour.

MR. SPEAKER : This is not a privilege motion which I ruled.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, all non-official Members of the House—those who are not Ministers—are not entitled to have discussion with the Officers in the Official Gallery.

I raise it as a point of decorum. This is not right.

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर जाकर बात कीजिए। यहां क्यों बात करते हैं ?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : This is not right.

MR. SPEAKER : I have told him.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : To-day you are very impatient, Sir....

MR. SPEAKER : Not allowed.

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय······

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

I have called upon Prof. Ajit Kumar Mehta.

---

**12.25 hrs.**

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### Reported rupees one crore income tax fraud unearthed involving certain leading industrialists of Delhi

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"एक करोड़ रुपये के आयकर की धोखा-धड़ी, जिसमें दिल्ली के कुछ प्रमुख उद्योगपति अन्तर्ग्रस्त हैं, का पता लगने के समाचार

तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : Mr. Speaker, Sir, on the basis of the complaints made by Hastimal Sancheti Memorial Trust, Pune and Pune Medical Foundation, Pune that one Shri V. Mehra of Delhi was collecting donation on their behalf without having any authority to do so, the residential premises of Shri V. Mehra were searched by the Income-tax Department on 13th and 14th September, 1983. The search resulted in seizure of foreign currency of the approximate value of Rs. 1.50 lakhs from the residence of Shri V. Mehra by the Enforcement Directorate who were also associated with the searches. The Enforcement Directorate have since initiated proceedings against Shri Mehra under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

**12.26 hrs.**

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The documents seized in course of the search supported the allegation made against him and it came to light that the Executive Director of a company of DCM Group and an astrologer of Delhi as well as certain other persons were involved in the racket. The modus operandi, by and large, is to open unauthorised bank accounts in the names of charitable organisations/trusts on the basis of the bogus resolution of otherwise, deposit the so-called donation given in the form of account payee cheques/drafts in these accounts from which they are shortly afterwards withdrawn in cash by the persons involved in the racket. Bogus donation receipts are issued to these donor organisations who claim deduction under section 35 (2A) [weighted deduction of donations made to scientific research association etc.] and Section 35CCA [Donations for Rural Development Programme] of Income-tax Act, 1961.

Consequently, searches were conducted on 26-11-1983 at the premises of these people as well as the banks where they were found to be maintaining accounts/lockers. Searches were also conducted at the office and residential premises of Dr. Charat Ram. Survey was conducted at the offices occupied by some executives at the premises of some companies of DCM Group. These searches resulted in seizure of bank drafts and FDRs of Rs. 85.20 lakhs in addition to incriminating documents. A number of lockers and 1 almirah in Delhi Safe Deposit Co. have been sealed. At other premises, jewellery, silverwares etc. of more than Rs. 13 lakhs have been restrained under section 132(3) of the Income-tax Act pending verification.

The searches, surveys and enquiries conducted revealed that some Companies of DCM Group have been misusing the provisions relating to Section 35(2A) and Section 35CCA of Income-tax Act, 1961, that Shri Prem Parkash, one of their top executives was brain behind this misuse, that S/Shri V. Mehra and P. P. Verma were actively working on behalf of the Group. The total amount of bogus donation debited in the books of accounts of various companies of the Group and the other concerns and individuals comes to Rs. 1.21 crores. In the wake of action by the Department entries to the tune of Rs. 62.5 lakhs have been reversed by some companies.

A number of other incriminating documents have also been seized and are under scrutiny.

**प्रो० अजित कुमार मेहता** : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी को हमने सुना। मगर उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं निकली जो समाचार पत्रों के समाचारों से भिन्न हो। मैंने उम्मीद की थी कि वित्त मंत्री की ओर से जो नई जानकारी मिली है उस पर प्रकाश डाला जाएगा।

करों की चोरी हुई और उसका पता लगा। ये भी पता चला कि किस प्रकार से पूना के मेडीकल कालेज का विज्ञापन निकला था, उससे सूत्र मिला और उस सूत्र के अनुसार इनकम टैक्स विभाग के लोगों द्वारा अनुसंधान करने पर इस बात की जानकारी मिली कि बड़े घराने के कुछ लोग, जिसमें डी० सी० एम० के श्री चरत राम,

श्री प्रेम प्रकाश जो श्री मदन मोहन श्रीराम के अधिकारी हैं, का नाम आया। इस प्रकार से अपराधियों की जड़ में इनकम टैक्स विभाग के लोग पहुंचने में सफल हुए। किन्तु दो तीन बातें इससे और प्रकाश में आती हैं कि इनकम टैक्स की धारा 35 (1), (2) और 35 (ए) तथा 80 (जी) का किस प्रकार इन लोगों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। यहां यह पता चला कि इन उद्योगपतियों द्वारा दो तरह से कर की चोरी की गई थी। एक तो यह कि ऐसे ट्रस्ट को धनराशि दान में देकर, जिनको इनकम टैक्स रीबेट की सुविधा है, एक बड़ी राशि उनसे वापिस ले ली गई। अपने व्यक्तिगत एकाउट में और दूसरा तरीका जो कर की चोरी का अपनाया गया वह यह कि बैंक में डमीज के मारफत फाल्स अकाउंट खोला गया और उन ट्रस्टों को बैंक ड्राफ्ट द्वारा या क्रास चैक द्वारा धन दान में दिया गया और फिर इन डमीज की मारफत वापस निकलवा लिया गया जिसमें निश्चित रूप से पता चलता है कि कुछ बैंक अधिकारियों की भी सांठ-गांठ रही होगी और इस रकम को तुरंत वापिस ले लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बैंक के ऊपर जिम्मेदारी है लोगों की पूंजी की रखवाली की; लोग अपनी पूंजी और बचत को बैंक में जमा करते हैं। पिछले दिनों बैंक धोखाधड़ी के बहुत से मामले प्रकाश में आए हैं और एक मामला यह भी है जिसमें बैंक का धोखाधड़ी का पता चलता है। तो मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बैंक में होने वाली धोखाधड़ी जिसमें बैंक अधिकारियों की भी सांठगांठ रहती है, उस पर उचित देखरेख होनी चाहिए, जिससे लोगों की पूंजी, सार्वजनिक पैसे की बरबादी न हो।

महाशय, दो दितम्बर से इस धोखाधड़ी के बारे में, कर की चोरी के बारे में खोजबीन आरम्भ की गई और जिसका परिणाम यह निकला कि सरकार को यह मालूम हुआ कि डेढ़ करोड़ के लगभग रकम के कर की चोरी हुई है। मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि इसमें डी० सी० एम० जैसी कंपनी का नाम आया है जिसके बारे में पहले भी बहुत कंट्रावर्सी खड़ी हो चुकी है।

इस कंपनी को हथियाने के लिए विदेश में रहने वाले भारतीय श्री स्वराज पॉल ने प्रयास किया और उसी दिन से इस कंपनी का नाम कंट्रोवर्सी में आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वराज पॉल, जिसमें बहुत से लोग प्रधान मंत्री का नाम जोड़ते हैं। जिस दिन से स्वराज पॉल अपने उद्देश्य में असफल हुए उसी दिन से इस उद्योग पर निगरानी बढ़ गई और उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी धोखा-धड़ी का पता लग गया। मैं इसमें किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। इस बारे में प्रसिद्ध पत्रकार श्री प्रेम शंकर झा ने अपना मंतव्य व्यक्त किया था :

It is a phenomenon where a commercial capital is trying to endeavour industrial capital....

दो पूंजीपतियों के झगड़े में मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। ऐसा लगता है कि उस षडयंत्र मे असफल होकर के उन्होंने कुछ लोगों की सांठ-गांठ से यह झगड़ा किया। सार्वजनिक धन का दुरूपयोग होने से बचाने के लिए कर की चोरी का पता लगाया जाता है। इसमें किसी के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। पता चला है कि डी० सी० एम० के श्री चरत राम ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अपर्णा आश्रम को चालीस लाख रुपये दान में दिए। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि अपर्णा आश्रम ऐसी कोई संस्था नहीं है, जिसे टैक्स रिबेट की सुविधा प्राप्त है। तीन साल पहले यह सुविधा दी गई थी। इस बात को गोपनीय रखा गया कि कब उनकी रिबेट की सुविधा समाप्त हो गई? यह भी पता नहीं कि चालीस लाख रुपया आश्रम को रिबेट की सुविधा प्राप्त होने से पहले अथवा बाद में दान के रूप में दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले यहां शून्य काल में इस बात की बहुत चर्चा थी कि फारेन हैन्ड्स होने से देश की सुरक्षा में खतरा हो रहा है। श्री धीरेन्द्र

ब्रह्मचारी की गन फैक्टरी के बारे में जो खबर छपी है, उससे पता चलता है कि फारेन हैन्ड कहां हो सकता है ? जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उनसे यह मालूम होता है कि जो राशि अपर्णा आश्रम को दी गई थी, कहीं इस तरह के धंधे को प्रोत्साहन देने के लिए तो खर्च नहीं की जा रही है ? एक सूचना और है, वह यह कि इस चालीस लाख के अलावा 85 लाख के बैंक ड्राफ्ट के बारे में एक पत्र पकड़ा गया। जिसमें यह कहा गया था कि इस 85 लाख रु० को अपर्णा आश्रम को दान में दे देना चाहिये। तो यह 25 लाख रु० किन कारणों से और किन प्रावधानों के लिये उस आश्रम को दिये जाने वाले थे, यह सचमुच में गोपनीय बात है, अभी तक पता नहीं चला।

इन तथ्यों के आलोक में मैं वित्त मंत्री जी से कुछ बातें जानना चाहूंगा :

(1) जब किसी प्रकार की कर की चोरी पकड़ी जाती है तो उस समय में तो बहुत शोर शराबा होता है, और अभी भी हुआ। किन्तु उसकी क्या परिणति होती है, क्या परिणाम होता है उस समय तक लोग उस बात को भूल जाते हैं और बहुत मर्तबा ऐसा पाया गया है कि जिस शोर शराबे के साथ काम शुरू किया गया वैसी परिणति अन्त में नहीं हुई। यह जो धन पकड़ा गया है यह किस प्रकार उपार्जित किया गया था जिसको कि एक विचित्र ढंग से सफेद पैसे को काले में परिणित किये जाने का उपाय किया जा रहा था ?

(2) डी० सी० एम० और ऐस्कार्ट्स पर कब्जा पाने के लिये श्री स्वराज पाल प्रयत्नशील थे अतः इस मामले में किसने क्लू दिया है इस मामले को पकड़ने के लिये ?

(3) श्री चरत राम ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अपर्णा आश्रम को पैसे दिये 40 लाख। उस आश्रम में कैसा अनुसंधान चल रहा था जिसके लिये यह धन दान में दिया गया ? क्या यह अनुसंधान विदेशी हथियार बनाने के ऊपर तो नहीं चल रहा था ? अभी जो जम्मू के इलाके में अपर्णा आश्रम की प्रयोगशाला है जहां पर अनुसंधान चलाने के लिए यह पैसा दिया गया था तो वहां पर कैसा अनुसंधान चल रहा है ?

(4) अपर्णा आश्रम को 40 लाख रु० इन्कम टैक्स रिबेट की सुविधा समाप्त होने के पहले दान में दिया गया था या बाद में दिया गया ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : The hon. Member has brought almost every issue under the sun in this Calling Attention. Though he has said that he is not interested in holding anyone's brief, yet anyone who listens to his speech can come to the conclusion whose brief he is holding.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : I am not holding anybody's brief.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : If you listen to your speech you will come to know of that. Anyhow, I am ignoring that portion because it is not relevant so far as this calling attention is concerned.

The main contention is that certain people are taking advantage of certain tax concessions. It came to our notice. Firstly, certain advertisements were issued by the organisations whose names were involved in receiving the donations. Apart from that, he wanted to know the source. We never disclose the source either to Parliament or to the hon. Members because in that case, the source will dry up. So, I cannot answer from where we got the information.

But we received the information and as a result, first search took place on 13th and 14th of September. Thereater, when we conducted the raids, we seized certain documents and the scrutiny of those documents led to further searches and seizures which I have detailed out in my statement on 26th of November. These documents are being looked into and after the examination we shall be able to identify what types of evasion and avoidance have taken place. But one point I must share with the House that this is really disturbing when we give weight-

ed reduction, particularly for research and development purposes. For Rs. 100 expenses they get tax concession on Rs. 133. These concessions are extended with the hope that people will avail of these and will make contribution in the neal research work but if this type of things happen, I do not know how this country can progress. It is not that merely some racketeers are indulging in this type of activities but certain well-reputed organisations—at least so long well-reputed till they were caught—have indulged in these types of activites. For investigation sake, it would not be possible for me to give the details of these cases but I would like to inform the House that this is one of the reasons which prompted me to withdraw the cencession on rural development and many a Member raised their doubts that the entire rural development work will stop. At that point of time I did not have this information because this information came later on but I was hearing that in the name of rural development, concessions are being sought and actually rural development is not being done. So far as the tax administration is concerned, after all we shall have to keep in mind that their job in this respect is limited. When they look into that a company is spending, they look into whether they are maintaining their account books properly and whether the organisation which is receiving the concessions is eligible to have those concessions. So, from this point of view I do hope that after the detailed scrutiny and examination, it would be possible to look into it as to how we can take the corrective steps to plug the loopholes.

Another question the hon. Member referred to is whether some banks people are also involved in it. I myself have a doubt and I have already instructed my Department to look into it because after all there is a set procedure of opening an account. In the course of the examination, it was found that all the formalities which are to be done as per the rules of the banks, were not complied with and I have asked the Department to look into who is responsible for that. If somebody is responsible, definitely he will not be spared. In a number of recent cases in connection with other matters, the hon. Members have noticed that we have taken strong measures like removing the Chief Executive or top man in the bank, not the petty clerk or Branch Manager. In some cases, I have removed the Chairman and the Managing Directors of the banks....

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Whatever you say either sitting or standing, does not go on record. Other than Minister's reply, nothing will go on record.

(*Interruptions*)**

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I can tell you I have removed two Chairmen, not one...(*Interruptions*).

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : How do you select those Chairmen if you go on removing them ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : No question of that. That is, when things come to our notice and we find that they are involved. It is neither my will nor your will. It depends on when we can establish something against them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He would not come in the selection, he will come in the removal only.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I said, I can hand over the entire banking sector to him if he is agreed to take it and manage it...(*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I only want loan without interest.

The hon. Member wanted to know about the Aparna Ashram, whether their eligibility to receive donations of the type under discussion has expired. I am told that it is upto

**Not recorded.

24th April 1983. So far as the procedures are concerned, hon. Members are well aware of them. In the course of this time, it has happened that as many as 700 trusts are entitled to concessions. After the receipt of the report of the PAC, I instructed that every application of this type of trust should be scrutinised and that when any application for renewal comes, we shall have to be selective. I am pretty sure some Members will say that great harm is being caused to the trusts by the withdrawl of these concessions...(*Interruptions*) You will not say, but when I withdrew the concession on t 17th September, it was made out....(*Interruptions*) Do not provoke me to say those things. You know the type of letters which we receive from the hon. Members and the type of requests which are being made. Anyway, this is the type of system under which we have to work. I am not disowning my responsibility. What I say is that there is scope for misuse, we shall have to be watchful and streamline the whole thing.

So far as this particular provision is concerned, I find from the list there is the name of Morarji Bhai Desai Grammonati Trust, Ramakrishna Vivekanand Mission and the names of some other reputed trusts. Those people did not even know that somebody was collecting funds on their behalf, depositing in a fake account and then withdrawing the money. So far as this particular case is concerned, we have evidence that it was a fake deposit. Whether they are entitled to have this eligibility to ask for this type of donation or not is a matter for detailed examination. Just at this point of time it is not possible for me to indicate it. In this case, the amount was deposited on the 30th September, 1982 and it was credited to the account of the recipient on the 20th October, 1982.

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण मामले पर आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है, इस पर हमारे मित्र ने चर्चा की और कुछ प्रश्न पूछे। हमारे देश के माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से जवाब दे दिया और कहा कि माननीय सदस्य के बहुत से प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज के इस कालिंग एटेन्शन नोटिस में हम कौन-कौन सी बातों पर चर्चा करें। क्या इस कालिंग एटेन्शन नोटिस में हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके अपर्णा आश्रम की चर्चा करें? क्या इस कालिंग एटेन्शन नोटिस में हम भरतराम और चरतराम, देश के दुश्मनों की चर्चा करें? क्या इस कालिंग एटेन्शन नोटिस में हम फिल्म अभिनेताओं की चर्चा करें? क्या इस कालिंग एटेन्शन नोटिस में हम अन्य उद्योगपतियों पर चर्चा करें? भारत सरकार के फाईनेन्स मिनिस्टर ने कहा है कि श्री मेहता के सवालों का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। हम समझते हैं कि आज का यह कालिंग एटेन्शन नोटिस बहुत महत्वपूर्ण है। इस हाउस के साथ-साथ यह पूरे मुल्क के भविष्य का मामला है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Prof. Mehta has not objected to the answer of the hon. Minister. He is very much satisfied with the reply of the hon. Minister. You come to the Calling Attention.

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : आप हमारी बात सुनिए। हम इस पर बीस मिनट बोलेंगे और हमारे बीस सवाल होंगे। (**व्यवधान**) जब 20-सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारा बीस प्रश्नों का प्रोग्राम भी चल पड़े, तो क्या बुरा है?

मंत्री जी ने कहा कि हमने कुछ सूत्र प्राप्त किए और उन सूत्रों पर हमने खोजबीन की जिससे हमको मालूम हुआ कि यह इतना भारी घपला है। इस पर हम जांच करवा रहे हैं। बहुत सी बातें गोपनीय हैं। हम उसकी जांच करवाएंगे और वह हम बाद में बतलाएंगे।

सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि जो हमारे पास ये आंकड़े हैं और जो मंत्री जी का लिखित जवाब है उसके अनुसार हमें पता चलता है कि हस्तीमल संचेती मेमोरियल ट्रस्ट, पूणे और पूणे मेडिकल फाउण्डेशन, पूणे, इन दोनों ने एक सूचना

आपके यहां भेजी कि दिल्ली का वी० मेहरा नाम का कोई आदमी बिना किसी प्राधिकार के धन और चन्दा इकट्ठा कर रहा है, तब आपको सूचना मिली। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सूचना आपके इतने बड़े विभाग ने प्राप्त नहीं कि बल्कि पूणे की कुछ संस्थाओं ने यह सूचना आपके यहां भेजी और इससे इस स्कैंडल का पता चला। इसमें एक करोड़ पचास लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा और अन्य सब चीजों की घपलेबाजी पकड़ी गई। अब यह जांच कार्य आगे बढ़ा इस सूचना पर तो डी० सी० एम० के कार्यकारी निदेशक प्रेम प्रकाश और एक ज्योतिषी, जैसा कि ज्योतिष आजकल चल रहा है, उस तरह के ज्योतिषी, इस तरह के लोगों का एक गोल इससे स्पष्ट हुआ। इस तरह से मालूम हुआ कि जाली संकल्प न्यासों और खैराती संगठनों के नाम पर तमाम अनधिकृत खाते बैंकों में खोले जा रहे हैं, दान-दाताओं को जाली रसीदें छपंवा कर दी जा रही हैं और करोड़-करोड़, डेढ़-डेढ़ करोड़, दो-दो करोड़ रुपये वसूल किए जा रहे हैं, आयकर अधिनियम 1961 के 35,2 (सी), (सी) और 35 (जी) (सी) (सी) का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। यह सब मामला इन सब सूचनाओं के बाद प्रकाश में आया। भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई अपनी ओर से सूचना प्राप्त नहीं हुई। यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। 35,2 सी. सी. के बारे में जैसा मंत्री जी ने कहा, माननीय सदस्य सतीश अग्रवाल जी से कि हो सकता है आप सरकार के इस कदम की तारीफ करें लेकिन बाकी लोग नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि इस हाउस में चाहे यह पक्ष हो चाहे वह पक्ष हो, हर आदमी यह जरूर कहेगा कि किसी किस्म का घपला या किसी तरह की चोरी मुल्क के साथ नहीं होनी चाहिए। 35,2 सी. वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन की संस्थाओं के लिए नियम है इनकम टैक्स ऐक्ट का और 35, जी० सी० सी० में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दान वगैरह लेने का प्राधिकार प्राप्त है। यह मेमोरियल ट्रस्ट जिन लोगों ने लिए हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से या पूणे वाले ट्रस्ट के साथ जो घपला हुआ है या और जिन ट्रस्टों के साथ 1 करोड़ पचास लाख का घपला हुआ है जिस पर यह काल अटेंशन है; मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये जो ट्रस्ट हैं इनको किसने लाइसेंस दिए 35 जी० सी० सी० में? 35, जी० सी० सी० में जो लाइसेंस या उसमें आयकर की छूट दी गई वह किस अधिकारी ने छूट दी है और क्या यह छूट देने में उसने आयकर अधिनियम के नियमों का पूरा पालन किया है या नहीं किया है? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आज चार साल से किसी पार्टी विशेष के चहेते हैं। टेलीविजन पर उनका प्रोग्राम आएगा और चारों तरफ उनका प्रोग्राम आएगा और उनकी फैक्ट्री में बन्दूक भी बनेगी। वह बन्दूक मुल्क का संहार करने के लिए प्रयोग में लायी जायगी, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा वह रिसर्च कर रहे हैं जिसमें 35,2 सी० सी० के अन्तर्गत धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को यह छूट दी गई? 35, जी०सी० सी० में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दान लेने का प्रावधान है। वित्त मंत्री की ईमानदारी और निष्ठा पर हमें कत्तई सन्देह नहीं है, हम जानते हैं कि वह एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनको भी इस मुल्क की उतनी चिन्ता है जितनी हाउस में बैठे हुए दूसरे लोगों को है, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि जो आयकर में छूट दी गई है इन नियमों के तहत यह फर्जी छूट देने वाला अधिकार कौन है जिसने अपर्णा आश्रम को और दूसरे न्यासों को यह छूट दी है? अपर्णा आश्रम को दान में यह 40 लाख रुपया डी० सी० एम० की ऊषा इंटरनेशनल ब्रांच ने दिया। मैं जानना चाहूंगा कि यह 40 लाख रुपया जब बैंक में गया तो उस समय बैंक की क्या स्थिति थी? बैंक के अधिकारियों पर क्या बीती? आपने बैंक के बारे में अभी कहा। माननीय मंत्री जी अभी बैठे हुए हैं। दो साल पहले मैं मंत्री जी से बैंक के एक गबन के मामले में मिला था। यहां पार्लियामेन्ट के बैंक में मेरा खाता था, जिसमें जाली हस्ताक्षर करके साढ़े-बारह हजार रुपया निकाल लिया गया। मंत्री जी ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की और कहा, "शास्त्री जी आप बहुत अजीब बात कर रहे हैं, हम इसकी

जांच करवायेंगे।" डेढ़ साल तक जांच नहीं हुई। उसके बाद हम दूसरे मिनिस्टर से मिले—जनार्दन पुजारी जी से। उन्होंने भी यही कहा कि मैं तुरन्त जांच करवाता हूं। अन्त में उस फ्राड का वाराणसी से पता चला। इस बीच में वित्त मंत्री जी की एक बहुत लम्बी चिट्ठी आ गई कि समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो गया है। मैं जनार्दन पुजारी और प्रणब मुखर्जी में कोई भेद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वस्तु स्थिति को आपके सामने रखना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी को मालूम होना चाहिये कि आज देश की स्थिति क्या है। उसके बाद बैंक का आदमी वहां गया और उसने फ्राड करने वाले आदमी का गला दबोचा। जब पुलिस की मदद ली गई तो उसने बताया कि हमने जाली दस्तखत करके साढ़े-सात हजार रुपया निकाला है। बैंक अधिकारी ने कहा कि वह रुपया वापस करो। दो महीने पहले साढ़े-सात हजार रुपया हमको मिला। लेकिन उसके पहले हमारे पास फाइनेन्स मिनिस्टर का लैटर आता है कि यह जो रुपया गया है इसमें आपके परिवार का हाथ है या किसका हाथ है...

**श्री सतीश अग्रवाल** (जयपुर) : बाकी पांच हजार का क्या हुआ ?

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : बाकी पांच हजार तो गया, उस पर मजबूर होकर हमको सुलह करनी पड़ी।

अब मैं भरतराम, चरतराम और बंसी लाल की चर्चा करता हूं। इस सारे मामले में दो व्यक्तियों के नाम आये हैं—वी० मेहरा और प्रेम प्रकाश। आपने अपने जवाब में लिखा है—

> "की गई तलाशियों, सर्वेक्षणों और पूछताछों से इस बात का पता चला है कि डी० सी० एम० समूह की कुछ कम्पनियां, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2क) और धारा 35 गग क से सम्बन्धित उपबन्धों का दुरुपयोग करती रही हैं, यह कि इस दुरुपयोग के पीछे श्री प्रेम प्रकाश का दिमाग काम कर रहा था जो उनके प्रमुख कार्यकारियों में से एक हैं यह कि श्री वी० मेहरा और श्री पी० पी० वर्मा, समूह की ओर से सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे।"

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं—ये जो भरत राम, चरत राम और बंसी लाल वगैरह-वगैरह हैं—आप भी जानते हैं और सारा देश जानता है कि डी० सी० एम० संस्थान इनके हैं। इनके जिन दो कर्मचारियों का नाम आप कुबूल कर रहे हैं वे किसके लिये काम कर रहे थे? ये इन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे और इसका लाभ भी इन्हीं लोगों को पहुंच रहा था—क्या ऐसे पूंजीपतियों को गिरफ्तार करके हवालात में भेजने का काम करेंगे? इनके नौकरों के खिलाफ जो कार्यवाही होनी है, वह तो होगी ही, लेकिन जिनके लिये ये कर्मचारी काम कर रहे थे, जो इस तरह से देश को धोखा दे रहे थे, आप उनको गिरफ्तार करेंगे या नहीं?

इन्कम टैक्स का जो मामला है, इसी सम्बन्ध में हमारे सामने एक केस और आया है। यह एक एप्लीकेशन है जिसकी कापी प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के पास भी गई है। सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग है और उसमें अशोक जैन और आलोक जैन जो दो उद्योगपति हैं, वे मालिक हैं। इन लोगों ने डबल खाते रखे हुए हैं और इन्होंने फर्जी खाते बना रखे हैं। मेघराज जैन, जो इनके यहां कर्मचारी था; उसने लिखा-पढ़ी की इन्कम टैक्स आफिसर के पास और इन्कम टैक्स कमिश्नर के पास और देश के प्रधान मंत्री और कुछ संसद सदस्यों को भी लिखा। जिसमें उसने बताया है कि किस प्रकार खातों का डुप्लीकेशन इनके यहां हो रहा है। उसने लिखा था कि इनको गिरफ्तार कीजिए और कार्यवाही करें। आपके नाम भी पत्र आया है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें एक करोड़ 17 लाख रुपया का घपला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक इन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। एसिसटेन्ट

डाइरेक्टर, इन्टेलीजेंस (इन्कम टैक्स), जयपुर, ने भी आपको पत्र लिखा है कि इतना बड़ा घपला हुआ है लेकिन यह मामला दबा हुआ पड़ा है।

इसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस देश में 1200 से अधिक बड़े घराने हैं और आपने राज्य सभा में एक उत्तर में यह बताया था कि 1969 का जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम है, उसकी धारा 27 के अन्तर्गत 1200 से अधिक पंजीकृत कम्पनियां हैं। इनमें से 95 पर 17 करोड़ 50 लाख 64 हजार रुपया बकाया है। आपने उसको वसूल करने के लिए क्या विधि अपनाई है। आपने इतना सारा रुपया वसूल करने के लिए कौन सी एजेन्सियां लगी रखी हैं और आप देश को कहां ले जा रहे हैं। आपने भी इस बारे में चिन्ता प्रकट की है लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन लोगों से रुपया वसूल न करके आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गरीब किसान से दो-दो सौ रुपया लगान के बाकी रहने पर किस तरह से उसको वसूल किया जाता है···

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you raise many points, the Minister will not be able to reply. He may be prepared to reply only to the Calling Attention. You are raising so many points. He may require notice.

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : मैं उसी पर बोल रहा हूं। यह कालिंग स्टेंशन में आता है। आज देश के किसान से जबर्दस्त रुपया वसूल किया जाता है लेकिन जिनके पास करोड़ों करोड़ रुपया इन्कम टैक्स का बकाया है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। आज गरीब, किसान और मजदूर पर ही कार्यवाही होती है। अभी बताया गया कि 10 पैसे के लिए एक बाबू को ससपेंड किया गया लेकिन जो करोड़ों करोड़ रुपया खाने वाले हैं, जिन पर करोड़ों रुपया बकाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती और उनको सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। उनको कच्चा माल मिल जाता है, लाइसेंस दे दिये जाते हैं और सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। आखिरकार यह सब क्या है। इस संबंध में मैं आप से यह कहूंगा। अभी एक रिपोर्ट आई है···

MR. DEPUTY-SPEAKER : You will not be getting a reply to all these questions. He may require notice for all that. He will be prepared to reply only to the Calling Attention.

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं···(**व्यवधान**)···

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can raise all those points on different occasion. The Calling Attention is on a specific subject. The rule is that you can only put one question. You are making it a general discussion. How can you expect the Minister to reply all the points that you are raising on this Calling Attention ?

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : मैं स्पेसीफिक प्वाइन्ट पर ही आ रहा हूं। इस तरह से होगा, तो हम इस कालिंग एटेंशन में भाग नहीं लेंगें और माननीय मंत्री जी हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर न दें।···(**व्यवधान**)··· हम इसमें भाग नहीं लेगें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let the Minister reply. I cannot help it. I have to conduct the proceedings of the House according to rules. I cannot act against the rules. You have already taken 15 minutes. You may have some satisfaction that you have said something. But you will not get a reply.

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : हमें जवाब नहीं चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : As a Member of Parliament, you can always write a letter to the Minister if you have got any specific case.

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : अब मैं एक बात माननीय वित्त मंत्री जी से बड़ी विनम्रता से

कहूंगा। इन्कम टैक्स में ये सब मामले हो रहे हैं और करों कि चोरियां हो रही हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि कम से कम उन लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि इस काम को देखते हैं और जो हमारे रक्षक हैं, वे ही भक्षक न बन जाएं। वाराणसी के अन्दर तीन कमिश्नर काम कर रहे हैं। इलाहाबाद में भी एक कमिश्नर हैं और कई एसिसटेंट कमिश्नर काम कर रहे हैं और इस तरह से 4-4 बड़े अफसर वहां पर काम कर रहे हैं। इलाहाबाद में जो कमिश्नर हैं, वे कहते हैं कि हम तो मुखर्जी साहब के रिश्तेदार हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पर बैठ कर 10 लाख रुपये का उन्होंने मकान बना लिया है। तीन साल हुए उनको वहां पर पोस्ट हुए। अब इनका वेतन तो दो हजार और सवा दो हजार रुपये होगा। आपको ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। जो रक्षक हैं, वे ही ऐसा काम करते हैं क्या आप इनके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हैं?… (**व्यवधान**) वाराणसी के अन्दर एक आर० के० सिंह सहायक कमिश्नर हैं और एक बी० एन० सिंह, एसिसटेंट कमिश्नर हैं। इन सब कमिश्नरों ने 5-5 लाख रुपये की बिल्डिगें बनाली हैं। हमारे पंडित जी बैठे हैं। इनको इसकी जानकारी हो या नहीं हो।

मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप इनकम टैक्स कमिश्नरों के ऊपर भी कार्यवाही करेंगे जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? जो उद्योगपति हैं, फिल्म अभिनेता हैं, फिल्म अभिनेत्रियां हैं, वे लोग मिलकर माल दबाते रहे हैं, उन पर भी आप कार्यवाही करेंगे या नहीं?

हमें आपकी सत्यनिष्ठा में कोई शिकायत नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि जब आपको भी देश से उतनी ही मोहब्बत है, जितनी कि हम सब को तो जो ये रक्षक बनाकर बैठाये हुए हैं और भक्षक का काम कर रहे हैं, रक्षण की बजाए भक्षण कर रहे हैं, क्या आप इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

हम चाहते हैं कि हमने जिन-जिन प्रश्नों को पूछा है, आप उनके जबाब दें। हमें डिप्टी स्पीकर साहब से यह शिकायत है कि हमको दो-तीन दफा टोक कर गड़बड़ कर दिया।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I am afraid, I do not know from where I should start.

MR. DEPUTY-SPEAKER : To what you should reply ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : It is a very personal matter, on which he made an issue. He could have simply asked me. I would have placed all the documents before you, if it becomes a practice in the course of the discussion that all extraneous issues including his personal matters he will bring in, it is not fair. What he did, what he wanted, was done.

I am sorry. I am also in Parliament for the last 15 years. We have never utilised the discussion on the floor of the House, to explain any personal issue, or to raise any personal issue. You want to take up this issue with the Minister and what you want to say is not understandable to me. I examined the case. I got it examined and he knows how those whom he trusted, how did they bungle. All these things are not for discussion ; a matter how the individual account of a Member of Parliament will be conducted or not, cannot be the subject of a discussion on the floor of the House. If he feels, he can bring the whole matter to you. You can ask for a discussion. I can ask CBI to look into it. If we discuss these matters, I do not know where is the end of it.

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है। मंत्री जी यह कह रहे हैं……

MR. DEPUTY-SPEAKER : Under what rule ? The Hon. Minister is clarifying certain issues which you raised. Please sit down.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is nothing of a point of order and anything like that. You have raised certain issues and the Hon. Minister is replying to them.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot ask the Hon. Minister to reply as you like. The Hon. Minister is entitled to reply as you are entitled to speak anything.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Personal matters of the Member should not be brought to the floor of the House. The floor of the House should not be utilised for that purpose. The Member should understand the subject. The subject is that some people are taking advantage of opening false accounts in the banks, withdrawing the money, showing that the money is to be deposited in a company which is entitled to have the benefit or who can give a receipt of donorship. Actually the money is not reaching them. Some fictitious accounts are being opened in the bank. Money is withdrawn by the donors themselves. This is the case. You are asking that when Rs. 40 lakhs are given to Aparna Ashram...

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please understand.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Please understand. You told how Rs. 40 lakhs were given to Aparna Ashram. Aparna Ashram is entitled to receive this donation. Rightly or wrongly, that is a different question. As per law, they are entitled to have it.

(*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I told you—again you are repeating—that their term expired on 24-4-83.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are 700 cases like this.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You have got no right to mislead the House as I have got no right to mislead the House. I got the information from my office. In reply to your supplementary, I corrected you and still you are repeating. The term expired on 24-4-83. I gave you the date on 20th October, 1982. These are the issues. Where is the question of the bank and how the bank would look into it ? I would like to know from the Hon. Member.

The bank persons' involvement is there if they had not complied with the rules and regulations which they ought to comply with according to the opening of bank account, and that is why I have said that, in a few cases, we found that when the accounts were opened, all the rules and regulations on opening an account were not complied with and these matters will be looked into.

Questions came : 'Why have you given this ?'. I have given to a large number of organizations, a large number of Trusts belonging to the Opposition Parties. 700 trusts are there. One, I mentioned—Morarji Desai Gramonnati Trust. Therefore, these organizations, over a period of years, had applied according to the rules and they were entitled to have it.

The hon. Member asked, 'Are you going to arrest Bharat Rams and Charat Rams ?'. If I arrest, you will come and ask, 'Where is your power under Income-tax Act' ? You yourself will say that. I am not talking of individuals. I am saying that I have no power under the law. If somebody evades taxes, I can catch hold of him, I can impose penalty on him, I can prosecute him and if under the prosecution he is penalised, whatever punishment may be there, the court will have to give the punishment.

Questions have also been raised why they are taking unnecessarily a long time. It takes a long time because of the fact that a large number of the seized documents are examined and thereafter assessments are being made and invariably people go to court ; in that, through the legal process, they delay it. So, ultimately we will always find that between detection and actual realisation there is a big difference. When you sit in the Public Accounts Committee, you take note of these facts and you draw your conclusions and give directions to us.

In regard to eligibility, as I mentioned in reply to an earlier question, I am also not very happy ; I am not quite sure whether all the trusts which are entitled to have this benefit are doing the real work or not. Till now the term of some of them has not yet expired, the approval period has not yet expired. I have instructed my Department that, when they renew their approval, they should examine each case and try to find out whether they are doing genuine work or some organizations like this are being created. We are fully aware of it. When we gave concession to trusts, I know, an industrial house created as many as 1400 trusts. You will be surprised to know this. I can inform my friend that as many as 1400 trusts were created just to take advantage of it.

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : उसको आप रिजेक्ट क्यों नहीं करते हैं ?

**श्री प्रणब मुखर्जी** : मैंने किया है, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूं।

In the last budget I said that I would not permit. The period was extended from time to time ; that which should have been implemented in 1973 is ultimately being implemented and even the extended period, till 30th November, was over. And I did not agree to extend the period even for a day, so that to some extent the misuse by creating trusts is being avoided. In certain other areas also misuses are taking place. I would not say that everybody is doing this misuse. Some are also doing real and genuine work. For instance, when I suggested that no contribution would be made to the Rural Development Fund by 35CCA—it was a subject of discussion here ; that is why, it has relevance—I received a large number of representations, including from Members of Parliament, that some genuine organizations who are doing real, good work in the area of rural development will be deprived of this. I told them, I do appreciate that some genuine persons will suffer, but unfortunately because of these loopholes many people will take advantage of it and that is why, I said, instead of making donations to individuals, make to this type of organizations ; I indicated that you would be entitled to have the concession if you contributed to the National Rural Development Fund which would be administered by the Government. Whatever it is, good, bad or indifferent, Government is, after all, accountable for each and every work to Parliament and there should be some accountability.

So, that thing we have already done. In regard to the other matters, as I mentioned to you, in the course of the investigation, it would not be possible for me to indicate in details. He referred to Jaipur Udyog. I will have to check up. So far as my present information goes, it is not under the control of Mr. Jain. You referred to a cement factory of Jaipur Udyog. But, what exactly is the position, I will have to check up. Already I have received a representation from there. I will examine it.

In regard to the corruption of the tax officials, we got a complaint. I will take action. If you just look at the report of the CBI or the Vigilance Commission which is placed on the Table of the House, actions are being taken against a large number of officers. It is not that always actions are not taken. Actions are being taken also on the complaints of the Members of Parliament. But, because of certain obvious reasons also, we tell them that we are taking action because we have received some complaints from some of the Members. But, when we receive the complaints, we get them examined and action is taken. Sometimes when actions are taken, if we do not find them to be true on the basis of the complaint, action could not be taken. Ultimately, even, if we take action, somebody will go to the court. I have to justify that. Even in regard to any transfer, posting or promotion, we have to justify that in the court of Law.

Therefore, in these matters, we have to proceed slowly. If he has any specific complaint, definitely, I will look into it. Whatever be his relation or whatever be his connection, that will not stand in the way of taking appropriate action if he is found guilty.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Jaipal Singh Kashyap. There are two more speakers.

You will get five minutes each. We shall adjourn after you all finish. I know you will be as brief as possible. That is why I have given you five minutes. Shri Jaipal Singh Kashyap.

**श्री जयपाल सिंह कश्यप** (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए कालिंग अटेन्शन तो एक बहुत ही छोटे दायरे की चर्चा है। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिए इस पर एक पूरी चर्चा सदन में होनी चाहिए। यह मामला देश में काले धन से पूंजीपतियों, बड़े घरानों और जो व्यापारिक समूह हैं, उनको बैंक द्वारा संरक्षण देने की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कुछ नए पन्ने भी खुलते जा रहे हैं। अब तक तो हम भी टेलीविजन देखकर योग सीखने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और शिवा गन फैक्टरी का नाम भी इस चर्चा से जुड़ गया है। यह पता लग गया है कि किस तरह से काले धन को बढ़ाने में और इन्कम टैक्स की चोरी करने में··· (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : By bringing in other extraneous things in the Calling Attention, the seriousness of the pointed attention on the Calling Attention is lost. You must remember that. You must bring the Minister's pointed attention in the Calling Attention. So, you put a specific question to the hon. Minister. You may or you may not be convinced.

AN HON. MEMBER : Then, what is the point ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is between me and Shri Jaipal Singh Kashyap. He knows the rules and he will observe them. Now, Mr. Kashyap, you go ahead.

**श्री जयपाल सिंह कश्यप** : काले धन का संबंध देश की राजनीति, समाज, नैतिकता और अर्थव्यवस्था से जुड़ गया है। देश में कितना काला धन है जो बड़े-बड़े पूंजीपति बैंकों से चंदे के नाम पर इकट्ठा करके देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रहे हैं ? इनको तलाश करने में आपकी सरकार कहां तक सफल हुई है ? कितना धन आप जल्दी तलाश कर लेंगे ? मैं चाहता हूं कि आप कानून में ऐसा संशोधन कीजिए जिससे ये बड़े-बड़े लोग चाहे वे कितने ही बड़े घरानों से संबंध रखते हों, बचकर न जा सकें। बैंकों पर आपका कड़ा नियंत्रण होना चाहिए कि इस तरह के ट्रांजेक्शन्स की जानकारी सरकार को तुरन्त ही हो सके। अगर यह बात सामने न आती तो किसी को मालूम न होता कि किस तरह की गतिविधियां चलती हैं। क्योंकि पूंजीपति और व्यापारिक समूह तो एक दूसरे की बात को सामने नहीं लाते क्योंकि कहीं न कहीं किसी की उंगली दबी हुई है। अगर भरत राम-भरत राम का मामला सामने आयेगा तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का पर्दा भी उठ जायगा। तो क्या सरकार काला धन खत्म करने के लिए और इस पर नियंत्रण करने के लिए बड़े नोटों पर कोई पाबन्दी लगाकर, बैंकों के जो खाते हैं उन पर पाबन्दी लगा करके इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं या टैक्स इवेजन की कार्यवाही होती है उसको रोकने के लिए आप कोई कदम उठायेंगे ? और इस मामले में जितने जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि यह देश का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है इस पर कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे ताकि देश के लोगों को पूंजीपतियों और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के ट्रांजेक्शन्स के बारे में पूरी जानकारी देश को पता लग सके ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, I agree with the hon. Member that black money is no doubt a big menace to the economy and various efforts are being taken from time to time to tackle the problem. What we are discussing is just one of the *modus operandi* of generating black money. There is no denial of this fact. There are various measures which we are taking to tackle the problem. We are also intensifying the measures to bring them to book and in this way we are bringing the unaccounted income and wealth under the income-tax net. For instance, I will say about the average raids conducted by the Incometax Department. I am not taking here of the Customs and Enforcement raids, but I am taking only of

the Income-tax raids. These raids conducted by the Income-tax Department comes to the average of 4,000 per year nowadays. A couple of years back it was around 2,000 or 2,500 raids. So, this is one thing which I wanted to refer to.

When my colleague Mr. Venkataraman introduced a scheme you all objected to it and you said it will lead to more evasion of taxes and so on. But the fact is that by that scheme of Special Bearer Bonds an amount of nearly Rs. 1,000 crore has been brought into account. You may not agree with that scheme but the fact is, it has resulted in that much of black money being brought into account. So, all these measures are being taken to tackle this problem under the various schemes. But merely by enforcing strong measures, I am afraid, we cannot solve the problem. Because, apart from tightening the enforcement machinery and conducting raids searches and seizures, you will have to create the proper climate against the operation and transaction of black money. From my own experience, not during this period as Finance Minister, but much earlier also, what I found was this. They were detaining smugglers of foreign exchange racketeering under COFEPOSA. I know a particular case of one man who was detained. A top medical officer came forward and certified that if the man is not released on bail he will collapse. That man was released on bail by the court and immediately such a sickly person could have a joy ride of 50 miles ! This is what happened. What I want to point out is that those who certify like this do not take into account such types of nefarious activities indulged in by these poople. Those who certify may have their professional ethics ; they may have their professional commitments.

But they totally ignore their commitment to the society and the country. When these types of cases are there, you know, what types of lawyers are there to represent those cases, what big chartered accountants they get to prepare their accounts. If you expect that it is merely the job of the Incometax Officers, it would not help, though you may have that satisfaction that Government and the Incometax people will have to do that. And if we do not create social awareness or social injunction against the harm caused by the operation and generation of blackmoney, then we are not tackling the problem in the right earnest. Apart from the enforcement machinery, punitive machinery, and the legal steps, we shall have to create awareness among the people. Our friends from both sides of the House can help in creating some sort of awareness among the people about the menace of this problem.

I do agree with the general proposation that this is a serious problem and has to be tackled. We have been taking action, and have been providing you with statistical information and data on the action taken by us. In every session, in reply to the Starred and Unstarred questions, we have been giving you information, you have that in the reports of the Public Accounts Committee also. So far as the information is concerned, there is no dearth, but the question is how to create an atmosphere, where we can launch a frontal attack on the problem and get rid of this menace.

**श्री राजेश कुमार सिंह** (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री चरत राम का मामला शिकायत होने पर प्रकाश में आ गया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कुछ कार्यवाही की ? क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि कितनी विदेशी मुद्रा पकड़ी गई ? हमारा मुख्य प्रश्न यही है, हो सकता है कि मंत्री महोदय कह दें कि अभी बताने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन फैरा का उल्लंघन हुआ है ।

What are the details of all foreign tours, including purpose, dates, countries and parties visited undertaken by Shri Charat Ram, on foreign exchange permits issued in the names of DCM Ltd., the Jay Engineering Works Ltd., Shriram Refrigeration Ltd., Shriram Pistons and Rings Ltd., and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry in the years 1981, 82 and 1983 ?

श्री चरतराम के नाम से जो फारेन-एक्सचेंज परमिट इश्यू हुआ, इन्होंने सारा दौरा किया, पता

नहीं आपको इसकी जानकारी है या नहीं, लेकिन इसकी जानकारी जरूर करें और डिटेल्स प्राप्त करने का प्रयास करें।

इनका दौरा करने का क्या उद्देश्य था और क्या इन कंपनियों के नाम से फारेन एक्सचेंज का परमिट हासिल किया ? फैरा का उल्लंघन हुआ है, ये सिस्टर्स कन्सर्न हैं और सरकार आंख बन्द कर बैठी रही—

What are the companywise details of all foreign tours, (including purpose, names of persons, dates, countries/parties visited), undertaken on the blanket foreign exchange permits of Messrs. Shriram Refrigeration Ltd., Shriram Pistons and Rings Ltd. and Usha International Ltd., in the years 1981, 1982 and 1983.?

यह जानकारी हासिल होनी चाहिये। अगर अभी नहीं है तो बाद में सदन-पटल पर रखनी चाहिये। सरकार इस पर विचार करे क्योंकि शिकायत के बाद यह बात प्रकाश में आई है।

What are the visit-wise details of all foreign tours, including purpose, names of persons, dates, countries/parties visited, undertaken by the executives of the Jay Engineering Works Ltd. in connection with their fuel injection equipment project, so far.

यह बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है, जब किसी बड़े को पकड़ लेते हैं तो कहते हैं कि किसी की शिकायत आई, पकड़ लिया। यह सारा बहुत दिनों से मामला चल रहा है, यह नहीं होना चाहिये। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह इसकी जांच करायेंगे ?

Whether Charat Ram is a Director or a shareholder of these companies ? What is his liability ?

श्री चरतराम इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं, या शेयरहोल्डर हैं या क्या हैं ? इनकी लायब्लिटीज आप क्या फिक्स करते हैं ? उन्होंने इतनी हेरा-फेरी की है। उससे भी ज्यादा हेरा-फेरी आपके सामने आएगी। सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए कि हमने काम कर लिया है, अब भरतराम चरतराम स्वाधीन हो गए हैं।

स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की आज-कल बहुत चर्चा चलती रहती है, मैं भी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, मैं उसी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि स्वामी जी के पास तीन जहाज हैं, हवाई पट्टी है। उन्होंने जो किया है, वह जानें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This question was raised by many Members and the Speaker observed that the case was under investigation. Therefore, we should not discuss this.

**श्री राजेश कुमार सिंह** : मैं गन फैक्टरी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। इस सम्बन्ध में इसके रासपुटिन की याद आ जाती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि यहां पर भी वैसा ही कोई बन गया है। जारशाही के जमाने में रूस में वह ऐसा ही बड़ा आदमी था। मंत्री महोदय ने कहा है कि इसकी इलिजिबिटी एक्सपायर नहीं हुई थी। तीन बरस के बाद रिवाइज और रिव्यू करते हैं। जम्मू में आश्रम है और संचालन दिल्ली से होता है। उसे आपने कैसे अनुमति दे दी ? मंत्री महोदय ने कहा है कि 85 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट पकड़ा गया है। उसके एमाउन्ट को इस आश्रम को किस मद में किस सेक्शन के अन्दर देना चाह रहे थे ? जो 40 लाख रुपया दिया गया, क्या वह किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए दिया गया था वह जेनरल डोनेशन की कैटेगरी में था ? इसमें बड़ा कनफ्यूजन हो रहा है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का घपला चल रहा है। धारा 35(2) के अन्तर्गत सैपरेट एकाउन्ट रखना चाहिए—अगर कोई डोनेशन आ रहा है, तो रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट का पैसा अलग रखना चाहिए। क्या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का अलग एकाउन्ट था या नहीं, अगर नहीं था, तो क्यों नहीं था, क्या आपने इस बारे में कोई जानकारी की है ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I would like to just explain the tax evasion and tax avoidance which we are discussing. As the Hon. Member is aware in Income-tax, donations on rural development and donations on scientific research are permitted and the donars get the concessions on taxation. This is the whole scheme under 35 (2A) and 35(CCA). I am placing this because in the discussion the moot point has been lost sight of. The question is that certain companies are showing in their books of Account that they have made donations. Actually the companies in whose name they have shown the donations, they say they have not received any donation. On our examination also it is found that they have not received any donations. This is the starting point from where we started our investigation.

So far as Aparna matter is concerned, I have replied and I am repeating the fact that the draft of Rs. 40 lakhs was drawn on different accounts and it was drawn on 30th September 1982. It was deposited on 20th October 1982. And the date of approval there was upto 24-4-1983. That means when they received the donation they were eligible to have it. I hope the point is clear now. I have explained this because I find every time every questioner is raising this question.

The second point he wanted to know was about the status of Mr. Charat Ram and others whose companies have been mentioned in the list of donars.

For instance, one company Messrs. Industrial and Allied Sales Private Ltd. you will find here. Mrs Sumitra Charat Ram is the chairman. I do not know whether she is chairman or chair-person. Nowadays we use the term 'chair-person'. Then we have Messrs. General Sales Private Ltd. Dr. Charat Ram is the chairman. I am not mentioning the names of other Directors, as you wanted to know about Dr. Charat Ram. Then, we have Messrs. Meghdoot Enterprises Private Ltd.—Shrimati Sumitra Charat Ram is the chair-person. Messrs Karna Industries Private Ltd.—Mr. Deepak Sri Ram ; I do not know whether they are chairmen, I have got the names of five Directors.

Then Messrs. Madan Mohan Lal Shri Ram Private Ltd. : Dr. Bharat Ram is the chairman ; Dr. Charat Ram is also a member. There are other members. Another company is Usha International ; there also, Dr Charat Ram is the chairman. Apart from these, a few other companies are also involved.

In regard to foreign exchange, in one heading, as I had mentioned in the statement itself, foreign exchange worth Rs. 1.50 crores have already been recovered, resulting in the seizures of foreign exchange. In the first part of my statement, I have already mentioned it.

In regard to others, the hon. Member wanted to know—I am just coming to it—so whose account the chairmen or the other functionaries of the companies visited alroad —whether they were entitled to have the foreign exchange, whether foreign exchange was duly allowed or not. That is a matter which definitely I will have to examine. That information is not readily available. But as a general information, I can tell the hon. Members that certain companies whose export potentialities are very high, are normally issued the general foreign exchange because they are entitled to have some concessions as far as our export promotion is concerned—free foreign exchange permit it is called. I do not know whether they came under this scheme. That is a matter to be examined and looked into. Whenever I get the information, I will pass it on to the hon. Members.

———